

वन प्रबंधन को आधुनिक तकनोक से जोड़ा जाएगा, वनकर्मियों को करेंगे नई भत्तों : सीएम यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पदोन्नति प्राप्त वन अधिकारियों-कर्मचारियों को लगाए स्टार

वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने पदोन्नति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त किया

वन विभाग के कुल 4 हजार 506 अधिकारी-कर्मचारियों को मिली हे पदोन्नति

भोपाल/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जल, जंगल, वानस्पतिक संपदा और वन्यप्राणियों की रक्षा करने में वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों का योगदान महत्वपूर्ण

है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने नैसर्गिक सुंदरता के साथ मध्यप्रदेश को वनों का अनुपम साम्राज्य दिया है। ये वन भारत और दुनियाभर में मध्यप्रदेश की पहचान हैं। हमारे वनकर्म पुरी लगन से इसकी रक्षा करते हैं। प्रदेश के शासकीय सेवकों को पदोन्नति के फैसले का लाभ वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को भी मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में सुशासन की सरकार है। सुशासन के लिए हर क्षेत्र में युवाओं की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि पदोन्नति शासकीय सेवक का उसके काम के प्रति लगन और समर्पण का

सम्मान है। वन विभाग के 4 हजार 506 शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया गया है। सभी विभागों में कर्मचारियों को मिली पदोन्नति से मन संतोष से भरा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वन विभाग के लिए 25 हजार 389 पद स्वीकृत हैं। अभी 18 हजार से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। हम वन प्रबंधन को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए हमने पदोन्नति के साथ ही खाली हुए पदों को भरने के लिए नई भत्तों के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में वन विभाग में पदोन्नत शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों



द्वारा आयोजित आभार एवं अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री रामनिवास रावत भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन विभाग के मैदानी

अधिकारी-कर्मचारियों को 'प्रकृति पुत्र और ग्रीन सोलजर्स की संज्ञा देते हुए कहा कि उनके बीच आकर मन हर्ष से भर गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को भारत जैसे मेगा-बायोडायवर्स देश और समृद्ध जैव-विविधता की

विरासत मिली है। वन अमले के पुरुषार्थ से मध्यप्रदेश वन एवं वन्यजीव संरक्षण का रोल मॉडल बना है। प्रदेश की पहचान जल, जंगल और जीव से है और वन विभाग ने इनके संरक्षण में मिसाल कायम की है। इसी पुरुषार्थ के कारण मध्यप्रदेश को टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट, गिद्ध स्टेट और अब चीता स्टेट का गौरव मिला है। उन्होंने कहा कि पदोन्नति से वन विभाग में वर्षों के इंतजार का फल मिला है। जिन्हें पदोन्नति मिली है उनमें 188 सहायक वन संरक्षक, 2,821 वनपाल, 761 उप वन क्षेत्रपाल तथा अन्य संवर्ग के 736 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने सभी पदोन्नत अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनके परिजनों के सहयोग और त्याग के प्रति भी आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज मध्यप्रदेश वन जीवों के संरक्षण के मामले में पूरे देश अक्वल है। प्रदेश के जंगलों में अब भैंसों भी वापस आ चुके हैं। मध्यप्रदेश के वन और वन्यजीवों की दुनिया मुरीद है। हमारे वनकर्म पुरी प्रतिबद्धता के साथ जंगल, पहाड़, वन और नदियों की रक्षा करते हैं। वनकर्म हमारी वन संपदा की सुरक्षा की मजबूत दीवार की तरह हैं, जो वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ वन क्षेत्र में निवासरत आबादी की भी चिंता

करते हैं। मनुष्य का जीवन और जंगल एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमारा प्रयास है कि जैसा हमने पाया है, उससे और बेहतर हम भावी पीढ़ी को सौंपें। ईश्वर की कृपा से मध्यप्रदेश नदियों का मायका है। कोई ग्लेशियर नहीं होने पर भी हमारी नदियां जलराशि से सदैव समृद्ध रहती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास अगली पीढ़ी को सबसे अच्छा तोहफा सौंपने का सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि विकास तभी पूर्ण होगा, जब जंगल और जैव-विविधता सुरक्षित रहें, नदियां संरक्षित रहें और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षित हो।

न्यूज गैलरी

भोपाल में अब 15 मिनट में मिलेंगी ई-बसें:10 बस और दौड़ीं

भोपाल/नवप्रदेश। राजधानी भोपाल की सड़कों पर सोमवार से 10 इलेक्ट्रिक बसें और दौड़ने लगी हैं। इन्हें मिलाकर ई-बसों की संख्या 30 हो गई है। हर 10 से 15 मिनट में यात्रियों को निर्धारित स्टॉप पर बसें मिल रही हैं। फिलहाल 3 रुट पर बसें चलाई जा रही हैं। इस वजह से कोलार रोड, बावड़ियाकलां, बैरागड़, एमपी और आईएसबीटी के बीच बेहतर कनेक्टिविटी हो गई है। सभी बसें एमपी नगर से होकर गुजर रही है। जिससे नौकरीपेशा और स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिली है। जानकारी के अनुसार जिन जगहों से बसें गुजर रही हैं, उनमें बैरागड़, कोलार रोड, एमपी नगर, न्यू मार्केट, कोलार रोड, बावड़ियाकलां, सलैया, रोहित नगर, अशोका गार्डन, सुभाषनगर, कोहेफिजा, पीर गेट जैसे बड़े इलाके भी शामिल हैं। इनका न्यूनतम किराया 6 से 7 रुपए, जबकि अधिकतम 40 रुपए है। राजधानी में ई-बसों का बेड़ा बढ़ने से यात्रियों की संख्या भी बढ़ी है। पिछले सप्ताह ही 10 बसें और शुरू की गई थी और इसके बाद संख्या बढ़कर 20 हो गई थी। वर्तमान में 10 से 12 हजार यात्री हर रोज ई-बसों में सफर कर रहे हैं। सबसे प्रमुख दिवांगों के चढ़ने-उतरने के लिए हाईड्रैगलिक डोर हैं। जिनके जरिए वे ट्रायसिकल, व्हील चेंयर समेत बस में आ-जा सकेगे। इन बसों में जिस जगह हाईड्रैगलिक डोर है, उसके ठीक सामने इतनी जगह है कि दो व्हील चेंयर या ट्रायसिकल एक साथ खड़ी हो सके। दिवांगजनों के लिए पहली बार बस में यह सुविधा दी गई है। ई-बस की लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई करीब साढ़े 3 मीटर है, जबकि वर्तमान में जो सिटी बसें चल रही हैं, उनकी लंबाई 12 मीटर तक है। ऐसे में कई बार ये बसें तंग सड़कों और ट्रैफिक में फंस जाती है। ई-बसों के साथ ऐसा नहीं होगा। कुछ रुट पर ट्रैफिक जाम के हालात में जरूर दिक्कतें हो सकती हैं।

भोपाल में शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग पर धरना

4 दिन से निर्जल अनशन पर बैठे अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल जाने से इनकार

भोपाल/नवप्रदेश। मध्य प्रदेश में वर्ग-2 माध्यमिक और वर्ग-3 प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2025 में पदवृद्धि की मांग को लेकर भोपाल के नीलम पार्क में चल रहा अर्निश्चितकालीन धरना गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के अनुसार ब्यावरा निवासी नरेंद्र राजपूत पिछले चार दिनों से निर्जल अनशन पर बैठे हैं। सोमवार रात करीब 3 बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें लगातार चक्कर और कमजोरी की शिकायत हो रही है। धरना स्थल पर मौजूद अभ्यर्थियों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। आंदोलनकारियों के मुताबिक पुलिस प्रशासन पहले भी नरेंद्र को अस्पताल ले जाने का प्रयास कर चुका है, लेकिन उन्होंने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। नरेंद्र राजपूत का कहना है कि जब तक सरकार पदवृद्धि की मांग को लेकर कोई ठोस आदेश जारी नहीं करती, तब तक वे धरना स्थल से नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि यदि प्रशासन को उनके स्वास्थ्य की चिंता है तो धरना स्थल पर ही डॉक्टरों की टीम भेजकर स्वास्थ्य जांच कराई जाए। आंदोलनकारियों के अनुसार लगातार चार दिन से खाना और पानी नहीं लेने के कारण नरेंद्र की हालत कमजोर होती जा रही है। सोमवार रात तबीयत बिगड़ने के बाद साथी अभ्यर्थियों ने प्रशासन और मीडिया से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की अपील की। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की अपील की है। उनका कहना है कि वे लंबे समय से वर्ग-2 और वर्ग-3 शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। अब आंदोलन निर्णायक दौर में पहुंच गया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि वर्ग-2 में प्रत्येक विषय में 3 हजार पद बढ़ाए जाएं, जबकि वर्ग-3 में कुल 25 हजार पद किए जाएं। इसके साथ ही बढ़े हुए पदों पर दूसरी काउंसिलिंग कराने की मांग भी की जा रही है। अभ्यर्थियों का दावा है कि शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त पद शामिल नहीं किए गए। इसके कारण पात्रता और चयन परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने वाले कई अभ्यर्थी भी नियुक्ति से वंचित रह गए हैं। नीलम पार्क में चल रहे आंदोलन में कई महिला अभ्यर्थी अपने छोटे बच्चों के साथ भी धरने पर बैठी हैं। इंदौर की दीप्ति स्थल ठाकुर अपनी 5 और 8 साल की बेटियों के साथ धरना स्थल पर मौजूद हैं। वहीं सरोज कृष्णाहा अपने छोटे बेटे माधव के साथ आंदोलन में उठी हैं। महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि बच्चों के साथ पार्क में रहना मुश्किल हो रहा है। मच्छरों, पानी और बाॅशरूम की समस्या के साथ छोटे तालाब के किनारे होने से बच्चों की सुरक्षा की भी चिंता रहती है।

इसके बावजूद उनका कहना है कि पदवृद्धि का फैसला होने

बोले-कम रेट पर ठेके-भ्रष्टाचार से बिगड़ रही गुणवत्ता

एमपी की सड़कों की बदहाली पर बीजेपी विधायक ने उठाए सवाल

भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने मध्यप्रदेश में सड़कों की खराब हालत और निर्माण कार्यों में देरी को लेकर सरकार और विभागीय व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कम दर पर ठेके, निर्माण की गुणवत्ता में कमी और भ्रष्टाचार को सड़कों की बदहाली की प्रमुख वजह बताया है।



मध्यप्रदेश में सड़कों की खराब हालत और निर्माण कार्यों में देरी को लेकर भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पीडब्ल्यूडी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी कई सड़कों की स्थिति चिंताजनक है। कम दर पर ठेके लेने, निर्माण में गुणवत्ता से समझौता और भ्रष्टाचार का असर सीधे सड़कों की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। बिश्नोई ने यह भी कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सड़कों की

स्थिति से अवगत कराया। उनका कहना है कि ठेकेदार कम दर पर काम ले लेते हैं, लेकिन बाद में लागत और मुनाफे का संतुलन नहीं बैठने पर इसका असर निर्माण की गुणवत्ता पर पड़ता है। नतीजा यह होता है कि सड़कें जल्दी खराब हो जाती हैं और लोगों को परेशानी उठनी पड़ती है।

मझौली में तीन साल से अधूरी सड़क का उदाहरण
विधायक ने पाटन क्षेत्र की मझौली ब्लॉक की पौड़ा से पचैया सड़क का उदाहरण देते हुए कहा कि यह सड़क तीन साल से अधिक समय से बन रही है, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो सकी। इस दौरान तीन बार पेंटी कॉन्ट्रेक्टर बदले जा चुके हैं। मंत्री जी ने सड़कों का भूमिपूजन किया था, लेकिन उनका काम अब तक शुरू नहीं हो पाया। इसी तरह

मझौली नगर में करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये की सड़क का काम भी टेंडर प्रक्रिया में खल्ला हुआ है। बिश्नोई के अनुसार, छह बार टेंडर होने के बावजूद तकनीकी कारणों से प्रक्रिया ओगे नहीं बढ़ सकी।
पीएम ग्राम सड़क योजना में भी अड़चन
उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के रखरखाव को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि ठेकेदार कम दर पर काम लेने के बाद पांच साल के रखरखाव की जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। केंद्र के नए निर्देश के तहत जितने वर्षों का मेटेनेंस नहीं हुआ है, उतना मेटेनेंस का समय बढ़ा दिया जाए। इसे लेकर कुछ ठेकेदार हाईकोंट्र चले गए, जिससे नई टेंडर प्रक्रिया और पुरानी सड़कों के सुधार कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

विधायक बोले- जनता के सामने सबसे पहले विधायक आता है
बिश्नोई ने कहा कि सड़क, पानी और स्थानीय विकास से जुड़ी समस्याओं के लिए जनता सबसे पहले अपने विधायक के पास पहुंचती है। लेकिन जब प्रशासनिक स्तर पर काम नहीं होता

तो विधायक भी खुद को असहाय महसूस करता है। उन्होंने कहा कि यह केवल उनकी समस्या नहीं है, बल्कि पूरे मध्यप्रदेश के विधायकों के सामने ऐसी स्थिति आती है। उन्होंने हाईकोर्ट की ओर से निर्देशों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार को अदालत की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। बिश्नोई ने कहा कि समस्या को केवल राजनीतिक विरोध के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, इसके पीछे प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार बड़ा कारण है। उन्होंने सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के दावे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर इसकी वास्तविकता की गहराई से समीक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करनी है तो ठेके की प्रक्रिया से लेकर निर्माण, भुगतान और मेटेनेंस तक पूरी व्यवस्था की निगरानी जरूरी होगी। मंत्री और सीएम को कहने के बावजूद सुधार नहीं होने के सवाल पर अजय विश्वनोई ने कहा कि इसका मतलब साफ है कि अजय विश्वनोई कमजोर हो गया है।

रक्षाबंधन पर चेकिंग...मिलावट की शंका में 150 किलो मावा जब्त

भोपाल के आईएसबीटी और नादरा बस स्टैंड पर जांच; 166 किलो मिल्क केक भी मिला

भोपाल/नवप्रदेश। रक्षाबंधन और आगामी त्योहारों को देखते हुए भोपाल में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जांच अभियान चलाया। सोमवार को ढूँख्ख और नादरा बस स्टैंड पर बाहर से बसों के जरिए भोपाल लाए जा रहे मावा और मिल्क केक की जांच की गई। मिलावट या गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर 150 किलो मावा और 166 किलो मिल्क केक जब्त किया गया। नादरा बस स्टैंड पर नागपुर के रास्ते

भोपाल लाए जा रहे मावा और मिल्क केक की जांच की गई। 150 किलो मावा की कीमत 45 हजार रुपए है और इसकी बुकिंग अरीहत डेयरी भोपाल के नाम पर की गई थी। वहीं, 166 किलो मिल्क केक की कीमत 33 हजार रुपए आंकी गई है। इसकी बुकिंग सब्जी मंडी स्थित लवली स्वीट्स के नाम पर की गई थी। जब्त मावा और मिल्क केक के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों-विनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

एमपी ट्रांसको ने सीहोर में किया 50 एमवीए क्षमता का दूसरा पाँवर ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत: ऊर्जा मंत्री तोमर

भोपाल/नवप्रदेश। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्यप्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने सीहोर जिले की पारेणण व्यवस्था को और अधिक विश्वसनीय बनाते हुए 132 केवी सब स्टेशन, गोपालपुर में 50 एमवीए क्षमता का अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर स्थापित कर उसे ऊर्जीकृत किया है। साथ ही सब स्टेशन की ट्रांसफार्मेशन क्षमता बढ़कर 90 एमवीए हो गई है। ऊर्जा मंत्री तोमर ने बताया कि अब तक इस सब स्टेशन में केवल एक पाँवर ट्रांसफार्मर कार्यरत था। बढ़ते



विद्युत भार तथा पारेणण व्यवस्था की विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए दूसरा ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। दो पाँवर ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता से लोड प्रबंधन बेहतर होगा तथा किसी एक ट्रांसफार्मर के रखरखाव अथवा

तकनीकी कारणों से बंद रहने की स्थिति में भी विद्युत पारेणण प्रभावित नहीं होगा। एमपी ट्रांसको भोपाल के अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री राजेश शांडिल्य ने जानकारी दी कि इस ट्रांसफार्मर के ऊर्जीकृत होने के साथ ही सीहोर जिले में कार्यरत एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पाँवर ट्रांसफार्मरों की संख्या 27 हो गई है। जिले में एमपी ट्रांसको 11 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशनों के माध्यम से विद्युत पारेणण कार्य संचालित कर रही है, जिनमें 400 केवी के 14, 220 केवी के 88 तथा 132 केवी के 315 सब स्टेशन शामिल हैं।

केवी गोपालपुर, शाहगंज, सलकनपुर, इछावर, सीहोर, श्यामपुर और नसरुलखगंज सहित अन्य सब स्टेशन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नए ट्रांसफार्मर के ऊर्जीकृत होने से जिले की कुल ट्रांसफार्मेशन क्षमता बढ़कर 2607 एमवीए हो गई है। एमपी ट्रांसको प्रदेश में 417 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशनों के माध्यम से विद्युत पारेणण कार्य संचालित कर रही है, जिनमें 400 केवी के 14, 220 केवी के 88 तथा 132 केवी के 315 सब स्टेशन शामिल हैं।

बालाघाट में चिकित्सकीय एवं सहायक चिकित्सकीय मैनपावर सर्वोच्च प्राथमिकता से सुदृढ़ करें : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल/नवप्रदेश। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, मानव संसाधन, चिकित्सा उपकरणों की कार्यक्षमता और निर्माणाधीन स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने मौसम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वल्लेरेबल (संवेदनशील) क्षेत्रों में सुनियोजित कार्ययोजना के अनुसार चिकित्सकीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तत्परता से आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि

संवेदनशील एवं आवश्यकता वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने बालाघाट जिले में चिकित्सकीय एवं सहायक चिकित्सकीय मैनपावर के सुदृढीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक चिकित्सकों, नर्सिंग एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आईपीएचएस-12 के अंतर्गत करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध



दिए। उन्होंने रिक्त पदों की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यकतानुसार पदस्थापना एवं भर्ती संबंधी कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध

चिकित्सकीय उपकरणों की कार्यक्षमता की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य उपकरणों का उचित रख-रखाव किया जाए और खराब अथवा अनुपयोगी उपकरणों की समय पर मरम्मत

सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपकरणों की उपलब्धता के साथ-साथ उनकी कार्यशील स्थिति की भी नियमित निगरानी हो, ताकि मरीजों को आवश्यक जांच एवं उपचार की सुविधा निबांध रूप से मिल सके। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने निर्माणाधीन स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न हो

और कार्य पूर्ण होने के बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सचिवालय के लिए उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार के साथ उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग और संस्थानों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करना भी विभाग की प्राथमिकता होगी चाहिए। इसके लिए अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण एवं प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सुखवीर सिंह, आयुक्त स्वास्थ्य धनराजू एस, अपर संचालक स्वास्थ्य श्री मनोज सरियास सहित लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।



